



इक्कीसवीं सदी में भारत-इजराइल सम्बन्धों के बदलते आयामों का अध्ययन

प्रतिशा गौतम (शोधार्थी)

पर्यवेक्षिका- डा0 अनुपमा सिंह

(राजनीति विज्ञान विभाग)

आर्य कन्या डिग्री कालेज,

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज

सारांश :

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र होने के अधिकांश समय होने के पूर्व पहले से ही भारतीय तथा इजराइली समुदायों के बीच सम्बन्ध अस्तित्व में था। भारत की इजराइल नीति की जड़ें 1920 के दशक में देखी जा सकती थी, जब भारतीय राष्ट्रवादी आन्दोलन के नेताओं ने ब्रिटिश शासन के विरोध में फिलिस्तीनी हितों का काफी समर्थन करना आरम्भ कर दिया। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के इसी साझा विरोध के माध्यम से भारत तथा अरब नेताओं के बीच पहली बार राजनीतिक सहयोग स्थापित हुयी थी, नेहरू के विभिन्न साम्राज्यवाद विरोधी समूहों ने सन् 1927 में उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं का ब्रसेल्स सम्मेलन, में अरब राष्ट्रवादियों के साथ चर्चा की थी, इसी कारण से इजराइली राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं के प्रति भारत का नजरिया लंबे समय से पश्चिमी देशों के नजरिये के विपरीत रहा। भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू ने फिलिस्तीन के विभाजन तथा भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन में समान लक्षण देखा गया है। इन दोनों देशों के रिश्तों में विभाजन फूट डालों तथा राज करो की ब्रिटिश नीति से प्रोत्साहित दो राष्ट्रवादों के बीच की विभक्ति का परिणाम था। इसके परिणाम स्वरूप यहूदियों की समस्या एक अल्पसंख्यकों की समस्या थी तथा इसके समाधान में नेहरू ने संघीय सिद्धान्तों पर आधारित एक फिलिस्तीनी राष्ट्र (राज्य) की कल्पना की थी, यह समाधान पाकिस्तान के लिये मुस्लिम लीग की मांग के सम्बन्ध में उनके घरेलू दृष्टिकोण में सुसंगत था। भारत उन राष्ट्रों में से एक था, जहाँ यहूदी समुदाय के उत्पीड़न का इतिहास ही शून्य था। भारतीय राष्ट्रवादियों ने जायोनिवादी आन्दोलन का समर्थन नहीं किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जायोनिवादियों को पश्चिमवासी के रूप में देखने को मिली थी, जो साम्राज्यवादी ताकतों के समर्थन के साथ अरब राष्ट्रवादियों की कीमत पर एक नव-औपनिवेशिक राज्य बनाना चाहते थे।

हालांकि सन् 1953 में बम्बई में इजराइली वाणिज्य दूतावास के निर्माण तथा सन् 1955 में बांडुंग सम्मेलन में इजराइल के भाग लेने और भारतीय समर्थन के साथ संपर्क स्थापित करने के कुछ प्रयास सफल हुये।

15 अगस्त 1947 तथा 14 मई 1948 को क्रमशः भारत ता इजराइल का उदय संप्रभु देशों के रूप में उसी समय हुआ जब दो बड़े वैश्विक कर्ताओं, अमेरिका तथा सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ के बीच शक्ति का संघर्ष आरम्भ हुआ। अंतर-देशीय संबंध अनिवार्य रूप से इसी नये अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश से परिभाषित होने लगे तथा भारत और इजराइल जैसे परिधीय देशों के समझ मात्र तीन ही विकल्प रहे— वाशिंगटन के साथ गुटबंधन करना, मॉस्को के साथ गुटबंधन करना तथा दोनों महाशक्तियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रखने का प्रयत्न करना था। सोवियत विघटन 1991–1992 में पश्चिम एशिया की घटनाओं तथा इनके परिणामस्वरूप हुये प्रणालीगत बदलावों ने भारत को पश्चिम के प्रति, विशेष रूप से इजराइल के विषय में, अपनी विदेश नीति को रूपांतरित करने के लिये प्रोत्साहित किया।

शीत युद्धोत्तर परिवेश में भारत-इजराइल मैत्री को सुसाध्य बनाने में घरेलू स्तर के कारक भी महत्वपूर्ण रहे हैं। राष्ट्रीय कारक सन् 1947 से भारत की पश्चिम एशिया नीति का निर्धारण कर रहे हैं। पूर्व-विश्लेषित संरचनात्मक परिवर्तनों के समान ही 1990 के दशक के आरम्भ में उन राष्ट्रीय कारकों की प्रासंगिकता कुछ कम होती प्रतीत हुयी है। घरेलू पटल पर देखा जाये तो इजराइल के साथ सहयोग के महत्वपूर्ण आर्थिक तथा सैन्य प्रलोभन हमेशा रहे हैं।

भारत तथा इजराइल के बीच महत्वपूर्ण सामरिक समपूरकतायें एक लाभकारी सामरिक साझेदारी के विकास की व्याख्या कर सकती हैं। इजराइली सहायता की खोज करने हेतु भारत के पास प्रबल घरेलू कारण थे। भारत में एक महत्वपूर्ण सैन्य बाजार था, जो अपने क्षेत्रीय विरोधियों की तुलना में अपने गुणात्मक कमियों की पूर्ति हेतु नये समाधानों की खोज में था। दूसरी ओर इजराइल भी एक प्रतिष्ठित सैन्य उद्योग संकट में था, परन्तु सन् 1991 के बाद भारत-इजराइल संबंधों में आये आकस्मिक उद्भव को समझने के लिये व्यक्तिगत निर्णयों के साथ संरचनात्मक तथा राष्ट्रीय कारकों के अन्योन्यक्रिया का विश्लेषण निर्णायक है।

भारत-इजराइल संबंधों के भविष्य पर एक कारक के रूप में ईरान तथा मुंबई आंतकवादी हमलों के प्रभाव की स्पष्ट रूप में परिकल्पना कठिन है, परन्तु यह अंसभाव्य प्रतीत होत है कि वे कारक दोनों देशों के बीच एक अति फलदायी तथा संस्थापित सामरिक सहयोग का अंत कर देंगे।¹

29 जनवरी सन् 1992 को भारत और इजराइल ने पारस्परिक रूप से पूर्ण कूटनीतिक संबंध स्थापित कर लिये और आज दोनों देश आपसी भागीदारी की 28वीं वर्षगांठ के पड़ाव को पार कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच पारस्परिक स्तरों पर पल्लवित एवं पुष्पित हुआ। भारत और इजराइल दोनों ही अपने पड़ोसी देशों से आतंकित एवम् त्रस्त प्रतीत होते हैं, और दोनों देश अपने पारस्परिक सम्बन्धों को रणनीतिक संबंध के नजरिये से देखते हैं। सन् 1950 में भारत ने इजराइल को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी और इजराइल को अनुमति दी गई की वो बंबई में अपना दूतावास खोल लें ताकि भारत से हजारों भारतीय इजराइल जा सकें।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और इजराइल के बीच संबंध उन ऊंचाइयों तक पहुँच गये हैं, जो व्यक्ति विशेष से परे हैं। विदेश मंत्री के रूप में अपनी पहली इजराइल यात्रा पर पहुँचे जयशंकर ने यह टिप्पणी वहाँ के एक स्थानीय रूप से साक्षात्कार किया। जयशंकर ने कहा कि मेरा मानना है कि हम देश

के रूप में, राज्य व्यवस्था के रूप में, समाज के रूप में संबंधों के एक उच्च स्तर पर पहुँच गये हैं। इसलिये इस तरह यह हर उस व्यक्ति की सफलता का साक्ष्य है जिसने उसे परिवर्तन में योगदान दिया है। संबंध उन ऊँचाइयों तक पहुँच गये हैं जो व्यक्ति विशेष से परे हैं। हालांकि उन्होंने संबंधों को ऊँचाई पर पहुँचाने वाले व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका को भी मान्यता दी तथा कहा की हमें उन व्यक्तियों की सराहना करनी चाहिये जिन्होंने इसे संभव बनाया उन्होंने कहा की इसलिये मैं। यहाँ इजराइल में नई सरकार से सीधे बात करने आया हैं। जयशंकर ने यह बात सम्भवतः इस संदर्भ में कही की प्रधानमंत्री बेंजमिन नेतन्याहू के अपदस्थ होने के बाद दोनों देशों के सम्बन्धों पर किस तरह प्रभाव पड़ेगा।²

भारत-इजराइल समझौते के विभिन्न आयाम :

भारत-इजराइल सम्बन्ध भारत गणराज्य और इजराइल राज्य के बीच आर्थिक, सैन्य और स्थिरता को संदर्भित करता है। इजराइल का प्रतिनिधित्व नई दिल्ली में एक दूतावास और मुम्बई और बंगलौर में एक-एक वाणिज्य दूतावास के माध्यम से किया जाता है। तेल अवीव में अपने दूतावास के माध्यम से भारत का प्रतिनिधित्व करता है।

सैन्य सहयोग :-

इजराइल ने सैन्य के लिये द्रव्यमान और निगरानी उपकरण का उपयोग किया है और यह भारत के आतंकवाद विरोधी ग्रेटर को आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण भी देता है।

2014 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के चुनाव के साथ भारत-इजराइल ने गेमिंग के रूप में सहयोग बढ़ाया। मई 2014 और नवम्बर 2014 में मोदी के चुनाव के बीच इजराइल ने भारत के 662 मिलियन डॉलर की इजराइली लतायें और रक्षा करने का दिखावा किया। इजराइल के रक्षामंत्री माशो या लोन ने फरवरी 2015 में किसी इजराइली रक्षामंत्री की भारत की पहली अधिकारिक यात्रा की थी। 10 मई, 2017 को, भारतीय नौसेना के तीन जहाजों ने गम्रियों के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के निर्धारित समय से पहले हाईफाड बंदरगाह पर डॉक किया था, जहाजों में आई एन एस मुंबई आई एन एस त्रिशुला और आई एन एस आदित्य ने पोर्ट में प्रवेश करने के लिये इजराइली नौसेना के साथ एक नौसना अभ्यास में भाग लिया। चीन के बीच संबंधों के सम्बन्ध में भारत ने जुलाई 2020 में इजराइल से अतिरिक्त हथियार खरीदने की योजना की घोषणा की थी। इजराइली और भारत दोनों के रक्षामंत्री ने रिश्ते को मजबूत करने पर चर्चा की है जहाँ भारतीय रक्षा क्षेत्र में इजराइली रक्षा प्राधिकरण की अधिक भागीदारी को बढ़ावा देने की बात कही गयी थी।

कृषि सहयोग :-

2009 में दोनों देशों ने 50 मिलियन डॉलर का एक कृषि कोष शुरू किया जो कृषि और सूक्ष्म सिंचाई पर केन्द्रित था इसमें इंडो-इजराइल कृषि परियोजना बनाई थी। मार्च 2014 तक पूरे भारत में 10 केन्द्र संचालित हो रहे थे। जो इजराइली तकनीकी विशेषज्ञता का उपयोग करके कुशल कृषि तकनीकी पर किसानों के लिये मुक्त प्रशिक्षण सत्र की पेशकश कर रहे थे। कर्टिकल फार्मिंग, कनेक्शन इरिगेशन और सॉयल सोलराइजेशन कुछ ऐसे हैं जिसमें खेती आम, टमाटर, अनार और शाकाहारी पर केन्द्रित है।³

स्वास्थ्य क्षेत्र :

कोविड-19 महामारी प्रयास को रोकने के लिये भारत द्वारा इजराइल को आवश्यक दवाइयों की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जा रही है। भारत सरकार ने इजराइली दवा उद्योग के लिये मेडिकल टीम भेजने और कच्चे माल के लिये एन-95 फेस मास्क और अन्य चिकित्सीय उपकरणों की आपूर्ति सुनिश्चित करने को मंजूरी दी है।

जल संसाधन प्रबन्धन :

इजराइल की तुलना में भारत में जल की पर्याप्त उपलब्धता है लेकिन वहाँ का जल प्रबंधन भारत से कहीं बेहतर है। पानी की कम उपलब्धता के चलते इजराइल ने अवजल प्रसंस्करण और खारे पानी को मीठा बनाने की पद्धति में दक्षता प्राप्त कर ली है। इजराइल ने भारत में खारे पानी को पीने योग्य बनाने के लिये कई संयंत्र स्थापित किये हैं। इसके साथ ही इजराइल में कृषि, उद्योग, सिंचाई आदि कार्यों में पुनर्चक्रित पानी का उपयोग अधिक होता है, इसीलिये वहाँ के लोगों को पानी की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ता है। भारत जैसे विकासशील देश में 80% आबादी की पानी की जरूरत भूजल से पूरी की जाती है और यह भी सच है कि उपयोग में लाया जा रहा भूजल प्रदूषित होता है। इसके अलावा आपसी सहमति के क्षेत्रों के साथ-साथ अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग अलवर्णीकरण, जल संरक्षण के तरीकों व जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्रों में अनुभवों और विशेषज्ञता को साझा करने की जरूरत भी बताई गयी है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की समझौते :

मई, 2005 में औद्योगिक अनुसंधान और विकास पहल पर, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और इजराइल सरकार के उद्योग, व्यापार एवं श्रम मंत्रालय के बीच, द्विपक्षीय औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास सहयोग के गतिविधियों को बढ़ाने और ऐसी विशेष परियोजनाओं, जो औद्योगिक अनुसंधान और विकास को आगे बढ़ा सकें को चिह्नित और संवर्धित करने के उद्देश्य से एक संयुक्त विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर किये गये थे। इस संयुक्त विज्ञप्ति के अन्तर्गत भारत और इजराइल ने एक संयुक्त अनुसंधान एवं विकास कोष की भी स्थापना की है, ताकि, निवेश एवं संयुक्त-उद्यमों को प्रोत्साहित किया जा सकें।

संस्कृति एवं पर्यटन :-

इजराइल में भारत को एक सशक्त सांस्कृतिक परम्परा के प्राचीन देश के रूप में जाना जाता है और इजराइल में व्याप्त धारणा के अनुसार भारत एक वैकल्पिक पर्यटक गंतव्य देश है। इजराइल के युवा विशेष रूप से भारत के प्रति अधिक आकर्षित हैं। लगभग, 35,000 इजराइली अधिकांश युवक, अपने सैन्य प्रशिक्षण के पूरा हो जाने के बाद, भारत की यात्रा पर प्रति वर्ष आते हैं।⁴

आर्थिक और वाणिज्यिक सम्बन्ध :-

पिछले 25 सालों में दोनों देशों के बीच व्यापार 200 मिलियन डॉलर से बढ़कर 4 बिलियन डॉलर हो गया है। इसके परिणामस्वरूप भारत इजराइल का 10वाँ सबसे बड़ा व्यावसायिक सौदा बन गया है, भारत द्वारा इजराइल को प्रेस एवं धातु, रासायनिक उत्पाद, टेक्स्टाइल एवं टेक्स्टाइल लेख, जैसे व वनस्पति उत्पाद तथा खनिज उत्पाद का रूप धारण करता है। भारत द्वारा इजराइल से प्रजिडेट्स एवं मार्केटिंग विज्ञापन और खनिज उत्पाद केंस मेटल्स एवं ट्रांसपोर्ट डिवाइस का आयात किया जाता है।

रिलेक्सेशन का डी-हाइफनेशन :- डी-हाइफनेशन का अर्थ है की दो संयोजनों को डीलिंग करना अर्थात् उन्हें एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में देखता है। इजराइल के साथ भारत के सम्बन्ध फिलिस्तीनियों के साथ भारत के सम्बन्ध स्वतंत्र तथा अपने अलग-अलग आधारों पर विकसित होंगे। इससे भारत के राष्ट्रीय दावों को प्रभावी ढंग से संदेश देने के लिये नये लोग और विविधता के अवसरों को बल मिलेगा। शीत-युद्ध के दौरान हाइफनेशन एक अनिवार्यता थी, लेकिन बाद के दिनों में अरब जगत के रूठ जाने के डर से भारत का दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया जा रहा है।⁵

5 दिसम्बर भारत और इजराइल के बीच मुक्त व्यापार समझौता जून 2022 तक समाप्त हो जायेगा, इस सम्बन्ध में भारत में इजराइल के राजदूत नौरगिलोन ने कहा "यह एक बातचीत है विदेश मंत्री, एस जयशंकर की इजराइल यात्रा के दौरान जून में इसे हम खत्म करने के उद्देश्य से तथा इस चर्चा को फिर से तेज करने के लिये एक समझौता हुआ। हम इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं, उम्मीद है भी जून आखिरी तक हम इसे पूरा कर लेंगे।⁶

भारत और इजराइल ने स्वास्थ्य और औषधि के क्षेत्र में सहयोग के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किये जिसमें जलवायु के अनुकूल आधारभूत ढांचे के निर्माण में विशेषज्ञता साझा करना और हरित स्वास्थ्य सेवा, में सहयोग शामिल है इस समझौते पर इजराइल के विदेशमंत्री गैवीअश्केनाजी और इजराइल में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने हस्ताक्षर किये।⁷

भारत और इजराइल ने नेवोन्मेष समझौता किया— भारत और इजराइल ने ड्रोन रोबोटिक, कृत्रिम बहिमता और क्वांटम कम्प्यूटिंग समेत प्रौद्योगिकी और उत्पादों के संयुक्त रूप से विकास के लिये समझौता किया है जो उनके बीच बढ़ते रक्षा संबंधों का प्रतीक है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के बीच द्विपक्षीय नेवोन्मेष समझौता हुआ। उन्होंने बताया कि इस समझौते में स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों में अनुसंधान एवं विकास तथा नवोन्मेष को बढ़ावा दिया गया है। ताकि वे दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकी का

विकास कर सकें। रक्षा मंत्रालय ने समझौते को भारत और इजराइल के बीच बढ़ते प्रौद्योगिकी सहयोग मिल सके।⁸

भारत व इजराइल के मध्य राजनयिक संबंधों के पूरे 30 वर्ष हो गये तथा बदलते अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में इन दोनों देशों के मध्य सम्बन्ध स्थापित हुये है।⁹

3 नवम्बर, 2021 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन भारत और रक्षा, विकास निदेशालय रक्षा मंत्रालय, इजराइल ने पारस्परिक सहयोग हेतु एक नवाचार समझौते पर हस्ताक्षर किये इस समझौते का उद्देश्य दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों के विकास हेतु दोनों देशों के स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों में नवाचार और त्वरित अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना है। मई, 2021 में भारत और इजराइल द्वारा कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिये 3 वर्ष (2021–2023) की कार्य योजना पर हस्ताक्षर किया गया। भारत–इजराइल द्वारा भारत–इजराइल कृषि परियोजन उत्कृष्टता केन्द्र (Indo-Israel Agribultural Project Centes of Excellence) और भारत तथा इजराइल उत्कृष्टता गांव का क्रियान्वयन किया जा रहा है।¹⁰

भारत और इजराइल के मध्य समझौता :

भारत के दौरे पर आये इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजमिन नेतन्याहू तथा भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मध्य हैदराबाद हाउस में हुयी प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय वार्ता सफल रही तथा भारत–इजराइल के बीच साइबर सुरक्षा, रक्षा, फिल्म निर्माण, विज्ञान, तकनीक, तेल और सौर्य और निवेश के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौता हुआ।

द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी और नेतन्याहू ने साझा प्रेंस कॉन्फ्रेंस को सम्बोधित किया। सरकारी विज्ञापित में बताया गया है कि दोनों देशों के बीच फिल्म, स्टार्ट अप इंडिया, रक्षा और निवेश को लेकर सहमति बनी है। दोनों देशों के लोगों को करीब लाने के लिये इजराइल में जल्द ही एक इंडियन कल्चर सेंटर आरम्भ किया जायेगा।¹¹

वैश्विक महामारी को रोकने के लिये लागू किये गये पाबंदी के कारण बड़ी संख्या में दोनों देशों के नागरिक फंस गये थे, जिन्हें निकालने के लिये दोनों देशों की वायुसेना ने एक समझौता किया। इजराइल नवाचार के मामले में अग्रणी है और तकनीक के मामले में वैश्विक ताकत है, जबकि भारत रचनात्मक प्रतिभाओं विशेषकर वैज्ञानिकों आदि के मामले में काफी अग्रणी है। इजराइल को 'स्टार्टअप' हब के रूप में भी जाना जाता है। जो भारत की नई आईटी कंपनियों को आगे बढ़ने और बाजार में बनने में सहायता कर सकता है।¹²

निष्कर्ष :

इजराइल ने भारत में कृषि, सिंचाई और मध्य उर्जा के क्षेत्र में निवेश किया है और भारत में विनिर्माण के क्षेत्र में निवेश की संभावनायें तलाश रहा है। भारत और इजराइल के संबंध अगर रक्षा क्षेत्रों से इतर तेजी से और आगे बढ़ाने है तो इसके लिये दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता होना चाहिये। जिसके जरिये भारत की कई कंपनियाँ इजराइल की साझेदारी में वैश्विक स्तर पर पहचान बनाने की कोशिश कर सकती है।

इजराइल ने Reform, Perform Transform की मांग की थी, जिसे भारत ने काफी हद तक पूरा करने का प्रयास किया है। वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में दोनों देशों को द्विपक्षीय सम्भावनाओं तथा कारोबार और निवेश का दोहन करने के लिये और कदम उठाने की जरूरत है। भारत और इजराइल के बीच रिश्ते एशिया और मध्य पूर्व में तेजी से विकसित हो रहे भू-राजनीतिक वास्तविकताओं के आधार पर संचालित होंगे। ऐसे में इजराइल के बीच संबंध की व्यापकता और गहनता चीन-इजराइल संबंध जैसे नहीं है, जो मुख्य रूप से व्यापार और वाणिज्य से संचालित होते हैं। भारत को इन तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए की आने वाले वर्षों में चीन का ही प्रभाव बढ़ेगा। इसलिये भारत इजराइल सम्बन्धों में आर्थिक और वाणिज्यिक सम्बन्धों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। भारत और इजराइल ने दोनों देशों के बीच लम्बे समय से चले आ रहे रक्षा सहयोग को और गहरा करने के उद्देश्य से एक 'विजन स्टेटमेंट' पर हस्ताक्षर किये हैं। इस बयान पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और इजराइल के रक्षामंत्री बेनी गैरज के बीच हुयी बैठक में हस्ताक्षर किये गये थे। इजराइल के रक्षामंत्री ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में और निवेश करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

दोनों देशों के समक्ष आगे की राहें :-

- दोनों देशों के बीच संबंधों के कारण मुख्य रूप से शेयर जोखिम संबंधी वर्ष 1992 से कमजोर हो गये थे।
- भारतीय लोग इजराइल के प्रति सहानुभूति रखते हैं और सरकार अपने राष्ट्रीय हित के आधार पर अपनी पश्चिमी एशिया नीति को संतुलित एवं पुनर्गठित कर रही है।
- भारत और इजराइल को अपने धार्मिक चरपंथी पड़ोसियों की मधेता को दूर करने तथा सृष्टि परिवर्तन जल की कमी जनसंख्या विस्फोट एवं भोजन की कमी जैसे वैश्विक मुद्दों पर ग्रेबिट से काम करने की आवश्यकता है।
- अधिक आक्रामक और सक्रिय मध्य पूर्वी नीति सतय के मांग है ताकि भारत अब्राहम एकार्ड द्वारा धीरे-धीरे गिरते जा रहे हो भू-राजनीतिक पुनर्गठन का अधिकतम लाभ उठाये।
- भारत-इजराइल दोनों को अपने सम्बन्धों में मजबूती बनाये रखने के लिये शांति, वार्ता सहयोग से आपसी मसलों तथा पड़ोसी राज्य राष्ट्रों के भी सहयोग को बनाये रखें।

संदर्भ—सूची

- 1 सुमित गांगुली, भारत की विदेश नीति, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस प्रथम संस्करण हिन्दी 2018,(ISBNB NO) 978-0-19-909317.5
- 2 दैनिक जागरण (News paper)
- 3 <https://byius.com>.
- 4 Ministry of External Affiars (<http://nea.gov.in>)
- 5 Sansarlochan.in(<http://www.Sansrlochan.in>)
- 6 ANI News(<http://www.minews.in>.5 December 2021)
- 7 hindi.news 18. com (<https://hindi.news 18. com> 21/December 2020)
- 8 nav bhart times. in diatimes.com. 5 Nov. 2021
- 9 Sanskriti.com.
- 10 Current Affairs.2021-22
- 11 Current Affioars 2021.
- 12 News papers the Hindi, 2 May 20290

कीवर्ड— शांति सहयोग, आपसी मैत्रीपूर्ण समझौते, कूटनीति सहयोग, आपसी सहयोग, शांति वार्ता,

